भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

06 जनवरी, 2015

f=Lrjh; Qth ipk;r pqukoks dk cfg"dkj o Økfrdkjh turkuk ljdkjks dk etcr djus dk vkgoku

हमारी पार्टी दण्डकारण्य की जनता से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने एवं असली ग्रामसभाओं के जरिए गांव–गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकारों को चुनने, उन्हें मजबूत करने एवं उनका विस्तार करने की अपील करती है। पंचायत राज व्यवस्था ही दरअसल शोषक–शासक वर्गों के लुटेरे तंत्र को गांव स्तर तक मजबूत करने के लिए है। इन चुनावों से आम जनता की जिंदगियों में कोई खास बदलाव नहीं आनेवाला है। दरअसल हमारे देश में हर पांच साल में एक बार चुनाव इसलिए कराये जाते हैं कि शोषक–शासक वर्गों का कौन आदमी और किस पार्टी आगामी चुनाव तक जनता का शोषण–दमन करेगा। पंचायत चुनाव भी आम चुनावों का ही हिस्सा है।

आदिवासी इलाकों में पंचायत राज व्यवस्था का विस्तार करते हुए संविधान संशोधन के जरिए 'पेसा' कानून अमल में लाया गया था। ग्रामसभाओं की व्यवस्था की गयी थी। ग्रामसभाओं को कहने के लिए तो विशेष अधिकार दिये गये थे लेकिन चुनी हुई सरकारों के द्वारा ही संविधान के द्वारा प्रदत्त इन तमाम अधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रामसभाओं की अनूमति के बगैर सरकार भी आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकती। जबकि सच्चाई यह है कि ग्रामसभाओं के आयोजन व अनूमति के बिना या फर्जी ग्रामसभाओं का आयोजन करके बड़े औद्योगिक घरानों के लिए सरकारों के द्वारा कौडियों के भाव आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता की जमीनें छीनी जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ में रमण सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से लगातार वृहद उद्योगों, बड़े बांधों व बड़ी खनन परियोजनाओं के लिए देशी, विदेशी पूंजीपतियों के साथ समझौते करती आ रही है। कौड़ियों के भाव सार्वजनिक संपति को देशी दलाल बड़े पूंजीपितियों व विदेशी कंपनियों के हवाले करने की जनविरोधी, देश विरोधी कदम राष्ट्रीयता, देश भक्ति, स्वदेशी के नाम पर अमल किया जा रहा है। बस्तर संभाग के सातों जिलों सहित राजनांदगांव, रायगढ़ आदि आदिवासी बहुल जिलों में रावघाट, चारगांव, बुधियारी माड़, कुव्वेमारी, आमदाई, तुलाड, पल्लेमाड, सोनादाई आदि खदानों,टाटा, जिंदल, मित्तल, एस्सार, जैसे बड़े औद्योगिक घरानो के इस्पात संयंत्रों, मेंढकी, बोधघाट बहुउद्धेश्यीय बांध परियोजनाओं, संसाधनों की सस्ती लूट व सशस्त्र बलों की सरल आवाजाही के लिए रावघाट–दल्ली–जगदलपुर रेल लाइन, हवाई अड्डों, हेलीपैडों, वायुसैनिक अड्डों, माड़ पर सैनिक प्रशिक्षण शाला आदि के लिए करीबन एक लाख एकड़ जमीन जबरन अधिग्रहित करने की कोशिश में है, छग सरकार। इससे लाखों लोग, खासकर आदिवासी विस्थापित होंगे। जंगल नष्ट हो जायेगा। नदी–नाले प्रदूषित होंगे। पीने के पानी के लिए लोग को तरसेंगे। पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। बरसात की कमी हो जायेगी। कुलमिलाकर कहा जाए तो आदिवासी जनजीवन ही खतरे में पड़ जायेगी। ये तमाम परियोजनाएं अब तक जन आन्दोलन, जन प्रतिरोध व क्रांतिकारी जनयुद्ध के चलते ही रुकी हुई हैं, न कि पंचायत राज व्यवस्था के चलते।

तीसरी बार सत्तारूढ़ होने के बाद रमण सरकार अब बड़े पैमाने पर अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों को केंद्र से मंजूर करवाकर कैंपों व थानों का विस्तार करते हुए उपरोक्त तमाम परियोजनाओं को जन दमन के जरिए शूरु करने पर तुली हुई है। जन दमन का आलम यह है कि सरकारो के द्वारा सन् 2009 से जनता पर जारी नाजायज युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत संघर्ष इलाकों के गांवों पर लगातार हमलें जारी हैं। गांवों व घरों को जलाना, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, बेदम व सामूहिक पिटाई, ड़रा–धमकाकर व लालच देकर झूठा आत्मसमर्पण करवाना, आत्मसमर्पण न करने वालों को फर्जी केसों में फंसाकर जेलों में ठूंसना, झूठी गवाही या बिना गवाही के ही लंबी सजाएं देना आम बात हो गयी है।

छग सरकार ने चुनाव पूर्व के अपने तमाम लोक लुभावन वादों को जानबूझकर भुला दिया है। चुनाव खत्म होते ही पूर्व में मंजूर सभी राशन कार्डों को जब्त करके अवैध तरीके से छंटनी करके हजारों के कार्ड रद्ध कर दिये। गरीब जनता को 1 रु, 2 रु प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल देने की योजना के साथ चांउर वाले बाबा कहलाने वाला रमण सिंह अब वही चावल देने से बचने के लिए यह गरीब विरोधी कदम उठाया है। जनता को मिलने वाली सब्सिडियों में लगातार कटौतियां की जा रही हैं। धान का एक–एक धाना खरीदने, धान का समर्थन मूल्य 2100 रु प्रति क्विंटल करने, 300 रु का बोनस देने का सपना दिखाकर सत्ता में आने के बाद अब प्रति एकड़ सिर्फ 10 क्विंटल धान खरीदी करने, बोनस न देने, समर्थन मूल्य में नाममात्र की बढ़ोत्तरी की किसान विरोधी नीतियां अपनाने के पीछे दरअसल किसानों को धान की खेती करने से हतोत्साहित करने एवं रतनजोत जैसे वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देकर अनाज के लिए साम्राज्यवादियों पर निर्भर करने लायक देश को पराधीन बनाने की साजिश छिपी हुई है।

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति दयनीय है। गरीबों के इलाज के नाम पर आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में गरीब ग्रामीण, आदिवासी बेमौत मारे जा रहे हैं। नसबंदी नरसंहार, गर्भाशय कांड, मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड आदि सरकार की साजिशाना व आपराधिक लापरवाही एवं भ्रष्ट व्यवस्था के अनिवार्य नतीजें हैं। गरीब जनता खासकर आदिवासियों का जबरन या अनुचित तरीके से नसबंदी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे प्राचीनतम आदिवासी

जनजातियों में से कुछ के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। शिक्षा का निजीकरण लगातार जारी है। उच्च शिक्षा से गरीब लोग वंचित किये जा रहे है। बेरोजगारी बेरोकटोक बढ़ रही है। महंगाई आसमान छू रही है।

बजट में मंजूर सिंचाई परियोजनाओ में से आधे भी शुरू नहीं की गयी हैं। रोजगार के नाम पर सिर्फ सरकारी सशस्त्र बलों में ही जगह है। आदिवासी बटालियन के नाम पर संघर्ष इलाकों के युवक–युवतियों को इसलिए फोर्स में भर्ती किया जा रहा है ताकि संघर्षरत जनता व उसका नेतृत्व करने वाली माओवादी पार्टी, कुल मिलाकर क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा सके।

स्वावलंबन पर आधारित असली विकास, असली आजादी के लिए क्रांतिकारी जनयुद्ध के जरिए संघर्ष इलाकों में स्थापित की जा रही क्रांतिकारी जनताना सरकारों जो जनता के जनवादी राजसत्ता के अंग है, को उनके भ्रूण अवस्था में ही खत्म करने संघर्ष इलाकों को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। हर दिन कूंबिंग, हमले, लाठी, जेल, गोली, फर्जी केस, फर्जी आत्मसमर्पण, के नीच हथकंडे अपनाये जा रहा हैं। साथ ही संघर्ष इलाकों की जनता की एकता को विभाजित करके एक तबके को अपने पक्ष में करने, संघर्ष के पथ से दूर करने, भ्रष्ट करने, अपने तंत्र को मजबूत करने झूठी जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़े पैमाने पर अमल में लाते हुए उन्हें विकास योजनाओं का नाम दिया जा रहा है। दरअसल ये विकास की नहीं, विनाश की योजनाएं हैं। आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल बेहाल है। जबकि विकास योजनाओं का बड़ा हिस्सा, सड़क, पुल– पुलियों, मोबाइल टावरों, थाना, कैंपों के लिए खर्च किया जा रहा है। इन योजनाओं के नाम पर सरपंच, सचिव एवं अधिकारी व नेतागण मेवा खाते हैं। अपनी जेबे भरते हैं।

महिलाओं पर अत्याचार दिल्ली से लेकर झलियामारी तक बेरोकटोक जारी हैं। खासकर सरकारी सशस्त्र बलों के द्वारा आदिवासी ग्रामीण युवतियों व महिलाओं पर अनगिनत अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचारों को जन दमन के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की सरकारी नीति का ही परिणाम है, यह। दूसरी ओर सरकारों के द्वारा प्रायोजित व संरक्षित सामंतवादी कुसंस्कृति एवं साम्राज्यवादी जहरीली संस्कृति की ही देन हैं, ये अत्याचार। इसके लिए दोषी सरकार स्वयं है।

भाजपा सरकार देश को धर्मोन्मादी हिंदू राष्ट्र बनाने के आर.एस.एस के एजेण्डे पर काम कर रही है। अयोद्या में राम मंदिर निर्माण, धारा–370, कॉमन सिविल कोड़, शाला महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा की पढ़ाई, आदि मुद्धों को योजनाबद्ध तरिके से उछाला जा रहा है। जबरिया धर्म परिवर्तन, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य के बस्तर ब्लाक के मंधोता गांव में 39 ईसाई परिवारों को घर वापसी के नाम पर जोर जबर्दस्ती से हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। इस आयोजन का मुख्य अतिथि बस्तर का भाजपा सांसद दिनेश कश्यप रहा। लोहण्डिगुडा इलाके में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलें हुए हैं। घर वापसी या जबरिया धर्म परिवर्तन का शिकार होनेवालों में ज्यादातर दरअसल गरीब आदिवासी एवं दलित ही हैं।

गुजरात की भाजपा सरकार ने हाल ही में स्थानीय चुनावों में वोट देने को अनिवार्य बनाया है जो कि देश के नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। कल इसे देश भर में लागू करने का खतरा है। इस गैर–जनवादी व तानाशाहीपूर्ण हरकत का विरोध करना जरूरी है।

आजादी के 68 साल बाद भी ग्रामीण भारत के लोग मूलभुत सुविधाओं से वंचित हैं। तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस स्थिति में बदलाव चुनावों से नहीं, क्रांतिकारी जन संघर्षों, जनयुद्ध से ही संभव है। शोषक–शासक वर्गों की सत्ता की जगह उत्पीड़ित वर्गों – मजदूर, किसान, छोटे पूंजीपति व देशी पूंजीपतियों की सत्ता को स्थापित करना ही एक मात्र रास्ता है। इसीलिए आगामी त्रिस्तिरीय फर्जी पंचायत चुनावों का बहिष्कार करें। गांव–गांव में क्रांतिकारी जनता ना सरकारों का गठन करें, विस्तार करे, मजबूत करे। तभी जल–जंगल–जमीन व संसाधनों सहित तमाम प्राकृतिक संपदाओं पर जनता का अधिकार कायम होगा। सही आजादी, स्वावलंबन पर आधारित सही विकास संभव होगा।

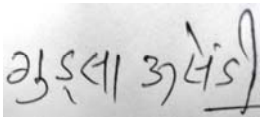

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)